महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पीयूडीआर को बदनाम करने की कोशिश की निंदा

नागरिक अधिकारों के पक्ष में उठती आवाज़ों को कुचलना बंद करो! पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पीयूडीआर पर सीपीआई (माओइस्ट) पार्टी का 'फ्रंटल' संगठन होने के दावे की कड़ी निंदा करता है। यह खुलेआम, भारत के एक सबसे पुराने जनवादी संगठन को धमकी देने और उसके काम पर रोक लगाने की कोशिश है।

पीयूडीआर और पीयूसीएल 1977 में आपातकाल की खिलाफत करने और उस समय गिरफ्तार किये गए लोगों की रिहाई में प्रमुख थे। उस समय से पीयूडीआर लोगों के अधिकारों के हनन के मुद्दे उठाता रहा है। इन मुद्दों में साम्प्रदायिक दंगों से लेकर, पुलिस हिरासत में मौत और बलात्कार, गैर-लोकतांत्रिक कानून और मृत्युदंड का विरोध, संगठित और असंगठित मजदूरों के अधिकार, फर्जी मुठभेड़, जातिगत दमन और अंतर्जातीय शादियों से लेकर आदिवासियों के विस्थापन शामिल हैं ।

पीयूडीआर ने भारत में पीआईएल के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है । 1982 में एशियाड खेलों के मामले में पीयूडीआर की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन पर कोर्ट में याचिका करने का अधिकार दिया था। पीयूडीआर उन संगठनों में से भी एक है जिनके द्वारा न्यायपालिका में किये गए प्रयासों के कारण पुलिस हिरासत में हुई हत्याओं के लिए मुआवज़ा मिलने की शुरुआत हुई थी।

जब भी पीयूडीआर की जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है, पीयूडीआर सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करता है, सरकारी विभागों से अपील करता है और न्यायपालिका या एनएचआरसी के दरवाज़े खटखटाता है, और एक सार्वजनिक राय बनाने के लिए इनके खिलाफ अभियान चलाता है । पीयूडीआर द्वारा हाल में चलाये गए अभियानों में कामनवेल्थ खेलों के निर्माण में लगे मजदूरों के लिए कानूनी रूप से निर्धारित मज़दूरी और सुरक्षित काम के हालातों की मांगों को लेकर अभियान शामिल हैं। यूएपीए के तहत होने वाले अन्याय को देखते हुए इस गैर-लोकतांत्रिक क़ानून को रद्द करने की मांग पीयूडीआर का एक अन्य अभियान है।

पीयूडीआर किसी भी राजनैतिक दल या पार्टी से सम्बद्ध नहीं है और यह इसके संविधान के तहत विशेष रूप से निषिद्ध है । यह अपने काम के लिए पैसा अपनी रिपोर्टों की बिक्री, सदस्यता शुल्क और समय समय पर अपने सदस्यों द्वारा दी गई सहयोग राशि से जुटाता है। यह किसी भी राजनैतिक दल, सरकार या संस्थानों से कोई धनराशि नहीं लेता है । अपनी फैक्ट-फाइंडिंग और अन्य कार्यकलापों के लिए इसके अपने सदस्य पैसों का योगदान देते हैं। अलग-अलग तरह के लोग और संगठन मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को लेकर पीयूडीआर के पास आते हैं, पर पीयूडीआर इन मुद्दों को उठाने का फैसला खुद करता है और इन पर अपने बलबूते पर काम करता है।

पीयूडीआर ने बिना झिझक किसी भी तरह के राजनैतिक विचारधारा वाले संगठन, पार्टी या समूह द्वारा लोगों के अधिकारों के हनन की निंदा की है। इसने बार-बार सीपीआई-माओइस्ट द्वारा नागरिकों की हत्याओं की निंदा की है - बारा हत्याकांड (1992), झारखण्ड में एक रेल में बम विस्फोट (2009), पुलिस अफसर फ्रांसिस इन्दुवर की हिरासत में मौत (2009), जमुई हत्याकांड (2010), नरेगा कार्यकर्ता नियामत अंसारी की हत्या (2011), झारखण्ड की एक ग्राम सभा को धमकियां (2012), छत्तीसगढ़ में पत्रकार साईं रेड्डी की हत्या (2013) आदि।

शुरुआत से ही पीयूडीआर ने मीसा, एनएसए, टाडा, पोटा और यूएपीए जैसे गैर-लोकतांत्रिक कानूनों का विरोध किया है और इन कानूनों से लोगों और समाज को होने वाले नुक्सान का दस्तावेज़ीकरण किया है - इसलिए पीयूडीआर ने 1990 में श्री एल.के.अडवाणी के खिलाफ एनएसए के लगाए जाने, कांग्रेस नेता कल्पनाथ राय के टाडा के तहत दोषी ठहराए जाने (1997), तमिल नेता वैको की पोटा के तहत गिरफ्तारी (2002), बीजीपी के युवा नेता वरुण गाँधी की एनएसए के तहत गिरफ्तारी, सिमी को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित करने आदि का विरोध किया है।

पीयूडीआर ने अपनी कोशिशों को उन लोगों के हितों के लिए केन्द्रित किया है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती ।इनमें शामिल हैं - वे छुट-पुट अपराधी जो अक्सर दिल्ली में पुलिस हिरासत में यातनाओं, हत्याओं और बलात्कार का शिकार होते हैं, निर्माण मज़दूर जो बेहद मामूली मज़दूरी और अनिश्चित हालातों में जीते हैं या फिर असंगठित मजदूर जो दुर्घटनाओं में घायल होते जाते हैं या जान से हाथ धो बैठते हैं और जिन्हें मुआवज़े या न्याय की कोई उम्मीद नहीं होती।

मानव अधिकार संगठनों को उन संगठनों की राजनीति से जोड़ने की कोशिश पहले भी होती रही है, जिनके मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे वे उठा रहे हों। जब पीयूडीआर और पीयूसीएल ने 1984 में सिखों के नरसंहार पर एक रिपोर्ट निकाली थी तो उसे कांग्रेस पार्टी से धमकियां मिली थीं और उसे खालिस्तानी संगठनों और उनकी राजनीति से जोड़ने का कुप्रयास किया गया था। यह याद रखना ज़रूरी है की उस समय के पंजाब के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से, तथ्यों को सामने लाने और इस तरह राज्य में हिन्दुओं के खिलाफ जवाबी हिंसा को रोकने के लिए हमारे संगठन का धन्यवाद किया था।

हम जनवादी अधिकार के काम को करने में निहित खतरों से पूरी तरह अवगत हैं ।ख़ास तौर पर तब, जब सत्ताधारी अपने कार्यकलापों द्वारा होने वाले नागरिक अधिकारों के हनन का विरोध करने वालों का मुंह बंद करना चाहते हैं । पीयूडीआर विवेक में अपनी आस्था को दोहराता है और यह आशा करता है कि लोकतांत्रिक संस्थान इस शर्मनाक कोशिश पर रोक लगाएंगें।

पीयूडीआर पुणे पुलिस द्वारा उसे कलंकित करने के अभियान की घोर निंदा करता है जिसमें हमारे वरिष्ठ सदस्य गौतम नवलखा और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं वरवरा राव, वर्नन गोंसाल्वेस, सुधा भरद्वाज, और अरुण फरेरा की गिरफ्तारी शामिल है । पीयूडीआर इस कुअभियान पर तुरंत रोक लगाने की मांग करता है।

शर्मिला पुरकायस्था
शहाना भट्टाचार्या
सचिव, पीयूडीआर

मोदी सरकार ने देश की सम्प्रुभता को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का पाप किया

गिरीश मालवीय की विशेष रिपोर्ट

दिल्ली में पिछले दिनों भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू की बैठक सम्पन्न हुई है, इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे।

इस बैठक में भारत का जोर मुख्यत: दो बातों पर था। पहला ये कि अमेरिकी नाराजगी को देखते हुए भारत ईरान से तेल नहीं खरीदें तो कहां जाए? दूसरा ये कि अमेरिकी आपत्तियों के चलते रूस से मिसाइल क्यों न खरीदें?

भारत अपनी जरुरतों का एक चौथाई तेल ईरान से मंगाता है।अभी जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं यह दाम ओपेक देश बढ़ा रहे हैं, अमेरिका के दबाव में आकर भारत ईरान से तेल मंगाना लगभग बन्द कर चुका है इसलिए उसे ओपेक देशो की मनमानी सहन करना पड़ रही है।और इस कारण पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। अमेरिकी दबाव में चाबहार पोर्ट पर भी भारत पीछे हट रहा है। रूस से किया गया एस400 मिसाइल प्रणाली का सौदा 'आखिरी चरण' में है लेकिन अमेरिका इस सौदे को न करने का दबाव बना रहा है।

लेकिन अमेरिका ने इन दोनों मुद्दों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अमेरिकी प्रतिनिधि माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत और अमेरिका पहली टू प्लस टू वार्ता के दौरान बड़े और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी।उन्होंने कहा कि बैठक मुख्य रूप से रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली और ईरान से तेल खरीदने की भारत की योजना पर केन्द्रित नहीं है।

तो फिर चर्चा किस बात पर की गयी ? और बैठक का नतीजा क्या निकला! यह भी समझ लीजिए।भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर इस बैठक में कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी ऐंड सिक्युरिटी अग्रीमेंट (कॉमकासा) पर हस्ताक्षर कर दिए है ओर मोदी सरकार की मांगों पर उसे ठेंगा दिखा दिया गया है।

अब यह कॉमकसा समझौता क्या है यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यह भारत की सम्प्रुभता को गिरवी रखने वाले समझौतों की दूसरी कड़ी है। किसी देश पर अपना सम्पूर्ण प्रभाव जमाने के लिए अमेरिका तीन रक्षा समझौतों को आवश्यक मानता है इसी में से एक समझौता है कॉमकासा (COMCAS) जो इस बैठक में किया गया।

दो अन्य समझौते हैं: लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics E&change Memorandum of Agreement :LEMO) और 'बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेटियल को-ऑपरेशन यानी 'बेका' (Basic E&change and Cooperation Agreement for Geo-spatial Cooperation: BECA)

लेमोआ पर मोदी सरकार अमेरिका से अगस्त 2016 में समझौता कर चुकी है जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकती हैं तीसरा समझौता 'बेका' पर भी वार्ता की शुरुआत हो चुकी है।

लेमाओ समझौते के तहत अमरीका जब चाहे तब हिंदुस्तान के अंदर अपनी फौजों को तैनात कर सकता है भारत के परिपेक्ष्य में यह बहुत गलत समझोता था अमरीकी सशस्त्र बलों को भारतीय नौसैनिक बंदरगाहों तथा हवाई अड्डो का अपने युद्ध-पोतों, जंगी जहाजों की सर्विसिंग, तेल भराई तथा उनके रख-रखाव के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देने का मतलब है हमारे देश द्वारा अब तक अपनाए जा रहे स्वतंत्र रुख से और किसी सैन्य गठजोड़ में शामिल न होने की उसकी नीति से पूरी तरह से हट जाना

लेकिन कॉमकसा का समझौता तो ओर अधिक खतरनाक है इसे पहले सिसमोआ (CISMOA) के नाम से जाना जाता था इस पर दस्तखत करने के बाद अमेरिका अपनी कम्पनियों द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का समय समय पर निरीक्षण करने का हकदार होगा। यानी वह जब चाहे मांग कर सकता है कि जिन हथियारों पर अमेरिकी संचार उपकरण लगे हैं वह उनकी जांच करेगा यह समझौता दोनों देशों के सैन्य बलों के संचार नैटवर्कों का आपस में जोड़ देगा भारत की कोई तकनीक सीक्रेट नही रह जाएगी।

यूपीए सरकार पर भी इन दोनों समझौतों को मानने का दबाव बनाया गया था लेकिन मनमोहन सरकार ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री, ए के अंथनी ने इस संबंध में स्पष्ट रुख अपनाया था।

इसे मोदी समर्थक भारत की कूटनीति कहेंगे लेकिन LEMOA ओर COMCASA पर हस्ताक्षर भारत की कूटनीतिक विफलता है क्योंकि किसी शक्तिशाली देश जैसे अमरीका की गोद में बैठ जाने को कूटनीति नहीं कहते, कूटनीति का अर्थ होता है सभी देशों के साथ अच्छे सम्बंध बना के हर देश का अपने सामरिक हितों के पक्ष में इस्तेमाल करना।LEMOA ओर COMCASA जैसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर के अमरीका जैसे किसी शक्तिशाली देश की सेना को अपनी सरजमी पर बुलाने को आत्मसर्पण करना बोलते हैं, कूटनीति नही।

स्पष्ट है कि भारतीय हितो से समझौता कर मोदी सरकार अमेरिका जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों की गोदी में खेल रही है।

डॉलर अंडरवियर नहीं अमरीकी डॉलर महंगा हुआ है

रवीश कुमार

आज 12 बज कर 03 मिनट पर डॉलर ने भारतीय रुपये को फिर धक्का दिया है। इस समय पर रुपये का भाव ऐतिहासिक रूप से नीचे चला गया। एक डॉलर 72 रुपये 55 पैसे का हो गया। वाकई अब श्री श्री रविशंकर से कहना होगा कि वे आएं और कुछ भभूत-वभूत छिड़कें ताकि डॉलर का नशा उतर जाएं। ध्यान रहे कि यहां एक डॉलर अमरीकी मुद्रा है और एक डॉलर गंजी अंडरवियर का भारतीय ब्रांड। इस डॉलर को कुछ नहीं होना चाहिए।

रामदेव के अनुसार मोदी जी के आने पर पेट्रोल 35 रुपया लीटर होने वाला था। महाराष्ट्र के एक शहर में पेट्रोल 89.97 रुपया लीटर हो गया है। डीज़ल 77.92 रुपया लीटर हो गया है। जनवरी से लेकर अब तक पेट्रोल 10 रुपया महंगा हो चुका है। बढ़ती कीमतों के बीच अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहेगी। यह बात कहते हुए स्पष्ट किया है कि अहंकार में नहीं कह रहे बल्कि काम के दम पर 50 साल सत्ता में रहेंगे।

कमबख्त अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने किस जनम का बदला निकाला है, पता नहीं। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि विपक्ष फेल हो गया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि सरकार पास ही पास है।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निदेशक केतन देसाई का केस याद नहीं ही होगा। वे आठ साल पहले निदेशक थे। इनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगे। मगर जांच की अनुमति नहीं दिए जाने के कारए एक एक करके सारे आरोप ख़ारिज होते जा रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक मामले में चार्जशीट दायर करते हुए सीबीआई ने कहा कि गुजरात सरकार ने इस केस में मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी है।

गुजरात सरकार ने मुकदमा करने की अनुमति क्यों नहीं दी, इस पर ज़्यादा दिमाग़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है यह भी एक तरीका हो भ्रष्टाचार से लड़ने का। मुकदमा या जांच की अनुमति ही न दो तो साबित ही नहीं होगा। फिर ख़बर लिखी जाएगी कि भ्रष्टाचार है कहां। जबकि इसी मामले में चार अन्य के खिलाफ मामला चल रहा है।

केतन देसाई पर मेहरबानी की वजह क्या हो सकती है? कौन है जो उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहा है? भ्रष्टाचार को लेकर तो ज़ीरो टालरेंस की नीति अपनाई गई है फिर अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। इस बार के चुनावों में देखिएगा, नोट कैसे पानी की तरह बहेगा और झूठ बोलने वाला सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा।

इस बीच ख़बर आई है कि नीरव मोदी ने जालिया फर्म बना कर बैंका 576 करोड़ रुपया अमरीका टपा दिया है। आप जानते हैं कि नीरव और 'हमारे मेहुल भाई' ने पंजाब नेशनक बैंक को 13,500 करोड़ का चूना लगाया है। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने 6519 करोड़ का लोन लिया। उसमें से 4000 करोड़ बाहर के देशों में टपा दिया। इतना पैसा कैसे टप गया, कोई पूछता भी है तो कोई बताता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार नीरव मोदी टपाने का यह खेल 2009-10 से कर रहा था जो 2015-16 तक जारी रहा।

प्रत्यर्पण निदेशालय का आरोप है कि इंटरपोल ही मेहुल चौकसी को सारी सूचनाएं दे रहा है।'हमारे मेहुल भाई' ने भारत की नागरिकता छोड़ एंटिगुआ की नागरिकता ले ली है। केतन देसाई, नीरव मोदी, मेहुल भाई। आप तीनों चिन्ता न करें। आप लोगों का टाइम अच्छा चल रहा है और अभी पचास साल और चलेगा।

मुरैना के देवरी गांव में एक डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाह को अवैध खनन में लगे एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया। मौके पर ही मौत हो गई। माफियाओं ने आधा दर्जन अधिकारियों को मार दिया है। 2012 में एक आई पी एस अफसर नरेंद्र कुमार को भी मार दिया था। हाल ही में अलकेश चौहान नाम के पुलिसकर्मी को भीम माफियाओं ने कुचल दिया था।

केंद्रीय खनन मंत्रालय ने लोकसभा में माना है कि अवैध खनन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर दो पर है। 2016-17 में मध्य प्रदेश में अवैध खनन के 13000 से अधिक मामले आए लेकिन एफ आई आर सिर्फ 516 में दर्ज हुई। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश।

आप चिन्ता न करें। बिहार में सृजन घोटाले में भी दायें बायें हो रहा है। कई हज़ार घोटाला का आज तक पता नहीं चला। बीच बीच में छापे की ही खबर आती है काम की नहीं। कौन कौन बच गया इस सवाल को छोड़ कर सभी हिन्दू एक रहें। मोहन भागवत ने कहा है कि हिन्दू एक नहीं होते हैं। शेर अकेला होता है तो कुत्ते भेड़िये हमला कर देते हैं। नौकरी नहीं मिली तो कोई नहीं। लेकिन 89 रुपये लीटर तेल भराकर उफ्फ तक न करने वाले हिन्दुओं का ऐसा अनादर होगा उम्मीद नहीं थी। वे चुप ही तो हैं। उनके चुप रहने के बाद भी भागवत कह रहे हैं कि कुत्ते भेड़िए शेर पर हमला करने वाले हैं। जबकि सारे लोग चुपचाप शेर के पीछे खड़े हैं ताकि उन्हें कोई कुत्ता भेड़िया न कहें। वैसे मैं समझ नहीं सका कि वे एक होने के लिए किसे कह रहे हैं। शेर को एक होने के लिए कह रहे हैं या कुत्ते भेड़ियों को एक होने के लिए कह रहे हैं।

ज़्यादा टेंशन न लें। जो कहा गया है उसे समझें। विचार करें। उम्मीद है आप समझ गए हैं मगर कमेंट समझने से पहले कीजिएगा। आई टी सेल काफी सक्रिय है। वो जो कहे वही मान लीजिएगा।